आर्थिक समीक्षा, 1993-94

-डॉ० अरुण कुमार

विश्व के किसी भी देश में जब भी संरचनात्मक समायोजन किया गया तो इनका प्रभाव आरम्भ में अच्छा नहीं रहा तथा निर्धन वर्ग को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। हमारा देश भी इसका अपवाद नहीं है, यद्यपि सरकार के उत्साह में कोई कमी नहीं है तथा यह माना जा रहा है कि आगामी चार-पाँच वर्षों में भारत स्वयं को उच्च समृद्धि निष्पादक के रूप में सुस्थापित कर लेगा तथा विश्व में आर्थिक क्षितिज पर नयी शक्ति बनकर उभरेगा। 1993-94 की आर्थिक समीक्षा में नयी आर्थिक नीति के तीन वर्षों का सन्तुलित मूल्यांकन किया गया है। इसमें बहुत सी उत्साहवर्द्धक बातों के साथ-साथ निराशाजनक तथ्य भी हैं। उत्साहवर्द्धक तथ्य तो यह है कि राष्ट्र 1991 के गम्भीरतम आर्थिक संकट से उबर गया है तथा पिछले तीन वर्षों में जो सुधार किया गया उनके परिणाम आने लगे हैं। जून 1991 में विदेशी मुद्रा भण्डार मात्र एक बिलियन डालर था जो अब बढ़कर लगभग 13 बिलियन डालर हो गया है। मुद्रा स्फीति की दर जो अगस्त 1991 में लगभग 17 प्रतिशत थी, फरवरी 1994 में घटकर लगभग 8.5% प्रतिशत ही रह गयी है। 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1.1 प्रतिशत थी जो 1992-93 में 4 प्रतिशत हो गयी।

बैंकिंग क्षेत्र में गहराते संकट से भी मुक्ति मिली, विदेशी व्यापार और विनिमय दर नीतियों की सुव्यवस्थित ढंग से जाँच-पड़ताल सुनिश्चित की, औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने की जटिल और दुरुपयोग की सम्भावनाओं से युक्त व्यवस्था को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया, विदेशी निवेश के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत उदार नीति को प्रारम्भ किया गया और पूँजी बाजार के नियंत्रण में दूरगामी परिवर्तन किये गये। भुगतान सन्तुलन की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। चालू लेखा घाटा वर्ष 1993-94 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से कम होने की आशा है। विदेशी प्रत्यक्ष और इक्विटी पोर्टफोलियो निवेशों के कारण 2.5 बिलियन अमरीकी डालर के अन्तर्प्रभाव की आशा है। विदेशी विनिमय मुद्रा प्रारक्षित निधियां 4 फरवरी, 1994 तक 10.9 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँच गयी थीं। भारतीय कम्पनियों द्वारा जारी इक्विटी एवं बाण्ड निर्गमों की विदेशी बाजारों में अच्छी प्रतिक्रिया हुई।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा तैयार किये गये राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 1993-94 में समग्र आर्थिक प्रगति 3.8 प्रतिशत। इस बीच कुछ बाधाएँ भी सामने आयीं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजकीय घाटे में सुधार हेतु रखे गये लक्ष्यों को पूरा करने में हुई भूल और मुद्रास्फीतिकारी दबावों की संबद्ध बढोत्तरी और सरकारी उधारों के लिए निवेश योग्य संसाधनों का पूर्व क्रय है। इसके अतिरिक्त निवेश और पूँजीगत वस्तुओं का उत्पादन दिसम्बर-मार्च, 1992-93 की गड़बड़ियों से अस्त-व्यस्त हो गया। अनेक कारणों से इस क्षेत्र में वृद्धि निरन्तर कमजोर रही है और सम्पूर्ण औद्योगिक निष्पादन घट गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रगति बाह्य क्षेत्र में देखी गयी। इस वर्ष के प्रथम 9 महीनों में डालरों में निर्यात वृद्धि 19.9 प्रतिशत हो गयी जो वर्ष 1991-92 में नकारात्मक रही और वर्ष 1992-93 में उसने 3.8 प्रतिशत की अल्प वृद्धि दर्शायी थी। 1993-94 के पूरे वर्ष के लिए व्यापार घाटा 1000 मिलियन अमरीकी डालर कम होने की आशा है, जो वर्ष 1990-91 और वर्ष 1992-93 के मुकाबले क्रमशः 9437 मिलियन अमरीकी डालर और 4106 मिलियन अमरीकी डालर था। चालू लेखा-खातों में भुगतान-सन्तुलन में घाटा वर्ष 1990-91 में 3.3 प्रतिशत तथा 1992-93 के 2.1 प्रतिशत के अस्थिर स्तर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से कम होने की आशा है। विदेशी प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो निवेश के बढ़ते अंतर्प्रवाह सहित चालू खाते में इन प्रतिकूल गतिविधियों से विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों का स्तर 4 फरवरी, 1994 तक 10.9 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँच गया।

वर्ष 1993-94 में वृहद् आर्थिक चिन्ता का मुख्य कारण राजकोषीय स्थिति में गिरावट का होना था। पिछले दो वर्षों में सफलता पूर्वक किये गये प्रयास की कुँजी केन्द्रीय सरकार के राजकोषीय घाटे में हो रही गिरावट थी, जो वर्ष 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 8.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1991-92 में 5.9 प्रतिशत थी और दिसम्बर-मार्च 1992-93 की गड़बड़ियों के कारण राजस्व में आयी तेजी से गिरावट के बावजूद 1992-93 में यह राजकोषीय घाटा नीचे रहा और जिससे सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत के बजट लक्ष्य से वास्तविक राजकोषीय निष्पादन में गिरावट आयी। वर्ष 1993-94 में केन्द्रीय सरकार के राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 4.7 प्रतिशत की गिरावट होने का अनुमान लगाया गया था। तथापि, अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाले राजस्व में लगातार कमी और खर्च पर भारी दबाव के कारण, घाटा काफी अधिक होने की आशा है।

उत्पादन

कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र में मूल्यवर्धित वृद्धि वर्ष 1993-94 (क्रे.सां.सं.) में 2.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। वर्ष की अनुकूलता के बावजूद, कृषि उत्पादन में वर्ष 1992-93 में प्राप्त अत्यधिक वृद्धि की अपेक्षा वर्ष 1993-94 में वृद्धि कम होगी। सार्वजनिक खाद्यान्न भण्डार दिसम्बर, 1993 के अंत में 22.8 मिलियन टन था, जो पिछले सात वर्षों की अपेक्षा अपने उच्चतम स्तर पर था, उच्च भण्डार स्तर लगातार अच्छी फसल, वर्षा और उच्च अधिप्राप्ति मूल्यों को प्रदर्शित करता है। अगस्त 1993 में पड़े सूखे के बावजूद जिससे कुछ राज्यों में धान की फसल प्रभावित हुई, इस वर्ष दो मुख्य अनाजों- चावल और गेहूँ का उत्पादन बढ़ने की सम्भावना है। 14.5 मिलियन टन पर दालों का उत्पादन लगभग 6.6 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि दर्शाएगा। कुल तिलहन उत्पाद में 3 प्रतिशत की वृद्धि होकर इसके 20.6 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर पहुँच जाने की सम्भावना है।

औद्योगिक क्षेत्र में निवेश का वातावरण और प्रत्याशाएँ मिश्रित रही हैं। दिसम्बर, 1993 तक जुटायी गयी कुल राशि लगभग 16850 करोड़ रुपये थी जो 1992-93 की तद्नुरूपी अवधि की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है। भारतीय कंपनियों ने भी यूरो-इक्विटी निर्गमों से 1992-93 में जुटाये 700 करोड़ रुपये (240 मिलियन अमरीकी डालर) की तुलना में लगभग 1100 करोड़ रुपये (लगभग 350 मिलियन अमरीकी डालर) जुटाए। नीति संबंधी सुधारों के संबंध में फ्रिज, जनरेटर, वाशिंग मशीन जैसी बिजली की वस्तुएं (व्हाइट गुड्स) और आटोमोबाइल क्षेत्रों में लाइसेंस हटाने से और प्रगति हुई। इससे उन उद्योगों की संख्या घटकर 15 तक पहुँच गयी जहाँ लाइसेंस अपेक्षित है। आधारभूत क्षेत्रों (विद्युत, कोयला, इस्पात, सीमेंट, कच्चा तेल और रिफाइनरी पदार्थ) ने जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का 281.81 प्रतिशत है, वर्ष 1993-94 की पहली तिमाही में वर्ष 1992-93 की इसी अवधि की तुलना में 5 प्रतिशत

की वृद्धि दर्ज की।

विस्तार के लिए कार्यक्षमता को प्रोत्साहित करने और संसाधनों को जुटाने के लिए आधारभूत क्षेत्रों में कई नीति संबंधी पहल की गयी। दूर संचार क्षेत्र में, मूल्यवर्धित सेवा निजी क्षेत्र के लिए शुरू की जा रही है। विदेश संचार निगम लि. ने विशाल यूरोइक्विटी ईश्यू अपनाकर अपनी इक्विटी में सरकार के हिस्से में और कमी कर अपनी नीति को अन्तिम रूप दे दिया है। देश में निर्धारित घरेलू विमान परिवहन सेवा से एकाधिकार को हटाने के लिए वायु निगम अधिनियम को जनवरी, 1994 में (अध्यादेश द्वारा) रद्द कर दिया गया है। एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स को उनके सांविधिक निगम के स्वरूप को पब्लिक लि. कम्पनियों में बदल दिया जाएगा। वर्ष 1992 तक हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में तेल अनुसंधान विकास और शोधन में भारत की निजी तथा विदेशी कम्पनियों के प्रवेश की अनुमति दी गयी थी। इन सुधारों के फलस्वरूप, कई घरेलू और विदेशी कम्पनियों के साथ अनुसंधान संविदाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि. नामक नई कम्पनी ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। एल. पी. जी. और मिट्टी के तेल के आयात को विभागीकृत किया गया एवं प्राइवेट फर्मों को इन उत्पादों को उपभोक्ता के लिए बेचने की अनुमति दी गयी।

मुद्रा और कीमतें

वर्ष 1993-94 के अधिकांश पखवाड़ों में मुद्रा आपूर्ति (एम-3) की वृद्धि की वार्षिक दर (12महीनों में) 14.2 प्रतिशत से कम रही, लेकिन अब इसमें वृद्धि होने के संकेत दिखाई दिये हैं। वित्तीय वर्ष 1993-94 (7 जनवरी 1994 तक) के दौरान वाणिज्यिक क्षेत्र के बैंक ऋण 6 प्रतिशत तक बढ़ गये जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 13 प्रतिशत थे। गिरती मुद्रा स्फीति की तर्ज पर जमा राशियों और ऋणों पर ब्याज दर घटायी गयी थी। 2 लाख रु. से अधिक ऋण बैंकों के लिए न्यूनतम ऋण दर को तीन प्रतिशत घटाकर वर्ष 1993 के दौरान 15 प्रतिशत कर दिया गया था। नकद प्रारक्षित अनुपात को दो चरणों में घटाया गया और इसे 14 प्रतिशत नीचे लाया गया। अक्टूबर 1993 में सांविधिक नकदी अनुपात वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के 37.75 प्रतिशत से गिरकर 34.75 प्रतिशत हो गये, निवल माँग और मियादी देयताओं में हुई किसी वृद्धि से संबद्ध विवर्धित सांविधिक नकदी अनुपात को 25 प्रतिशत नीचे लाया गया। पिछले वर्ष लागू किये गये मौद्रिक नियंत्रण से अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीतिकारी दबाव को रोका गया है। अप्रैल और मई, 1993 में वार्षिक मुद्रास्फीति (बिन्दु-दर-बिन्दु) 6.9 प्रतिशत तक गिर गयी और मार्च से जुलाई, 1993 के पाँच महीनों में औसतन 7 प्रतिशत रही।

राजकोषीय तथा वित्तीय घटनाक्रम

मार्च, 1993 को समाप्त हुए 21 महीनों में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.2 प्रतिशत तक घटाने में वृहद् आर्थिक स्थिरता संबंधी प्रयत्न सफल रहे। यहाँ तक कि प्रारम्भिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3.8 प्रतिशत तक तेजी से नीचे आ गया। तीव्र औद्योगिक बहाली को प्रोत्साहन देने और सामाजिक क्षेत्रों तथा गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लिए परिव्यय को बनाये रखने के उद्देश्य से वर्ष 1993-94 के बजट में राजकोषीय घाटे में गिरावट की दर संयत रही। कई कारकों से वर्ष 1993-94 में वसूली-लक्षित स्तर से काफी कम रही है। इन कारकों में औद्योगिक बहाली में मंदी, आयातों में मंदी और विदेशी मुद्राओं के मामले में रुपये के सतत् मजबूती और स्थायित्व शामिल हैं। व्यय पर पड़े भारी दबाव से मिलकर इससे राजकोषीय घाटे में बजट में निर्धारित लक्ष्यों की अपेक्षा उल्लेखनीय गिरावट होगी। वर्ष 1993-94 (7 जनवरी 1994 तक) के दौरान वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों से प्रतिभूतियों और राजकोषीय हुंडियों की बिक्री के रूप में सरकारी उधार 25.5 प्रतिशत तक बढ़ गये। यह वर्ष 1992-93 में प्राप्त 14.1 प्रतिशत की वृद्धि दर का लगभग दोगुना है। वर्ष 1993-94 के बजट में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का पूँजी आधार सुधारने के लिए 5700 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे ताकि उनको आपेक्षित पूँजी पर्याप्तता मानदण्ड प्राप्त करने में सहायता मिले। बैंकिंग व्यवस्था में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने कई निजी बैंकिंग व्यापारों को लाइसेंस प्रदान किये हैं। विदेशी बैंक अब नए बैंकों में 20 प्रतिशत तक इक्विटी रख सकते हैं। 'सेबी' ने प्राथमिक और मध्यवर्ती इक्विटी बाजारों में स्पष्टता बढ़ाने और निवेशक के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। नए निर्गम के प्रकटन और सूचीबद्ध अपेक्षाओं में सुधार किया गया और निर्गमों में शेयर आवंटन को और अधिक स्पष्ट बनाया गया। मर्चेन्ट बैंकर और स्टाक दलालों जैसे वित्तीय मध्यस्थों के लिए पूंजी पर्याप्त मानदण्डों को निर्धारित किया गया।

भुगतान संतुलन

इस वर्ष भुगतान सन्तुलन की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। अप्रैल-दिसम्बर, 1993 के दौरान निर्यात में अमरीकी डालर में 19.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आयात नीति के उदारीकरण और आयात शुल्कों को कम किये जाने के बावजूद आयात में 1.3 प्रतिशत की गिरावट देखी गयी। अप्रैल-दिसम्बर के दौरान जो व्यापार घाटा 732 मिलियन अमरीकी डालर था, वह वर्ष 1992 में हुए व्यापार घाटे की तुलना में पाँचवें भाग से कम है। 4 जनवरी, 1994 को भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां 10.9 बिलियन अमरीकी डालर थी। वर्ष के अन्त तक ये प्रारक्षित निधियां 12 बिलियन अमरीकी डालर के आस-पास हो सकती हैं। मई, 1991 में किये गये दो सप्ताहों के आयात की तुलना में यह राशि लगभग 6 महीने में किये गये आयात के बराबर है।

वर्ष के दौरान निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किये गये। 1 अप्रैल, 1993 को घोषित आयात-निर्यात नीति द्वारा मौजूदा नीति में संशोधन किया गया ताकि कृषि और श्रम-प्रधान क्षेत्रों, जिनके सम्बन्ध में देश की स्थिति अपेक्षाकृत बहुत अनुकूल है, से निर्यातों पर बल दिया जा सके। निर्यातों की निषेध सूची में काफी काट-छांट की गयी। निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई. पी. जेड), 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों (ईनीयू) और इलेक्ट्रो हार्डवेयर टेक्नालॉजी पार्क्स (ई.एच.टी.पी.) के जरिये निर्यात हेतु उपलब्ध सुविधाओं और प्रोत्साहनों को मजबूत बनाने के लिए अनेक उपाय किये गये। हाल ही में समाप्त उरुग्वे बातचीत से भारत विकसित देशों के बाजारों जहाँ टैरिफों में और कमी होगी, किये जाने वाले निर्यातों में वृद्धि कर पायेगा। 10 वर्षों में "मल्टी फाइबर" व्यवस्था की विभिन्न चरणों में समाप्ति से हमारे परिधान और वस्त्र निर्यातक उन उत्पाद वर्गों में, जहाँ उन्हें प्रतिस्पर्द्धा लाभ हो, बाजार में अपने हिस्से को बढ़ा पाने में समर्थ हो पायेंगे।

इसी प्रकार, विकसित देशों में कृषि को दी जा रही सब्सिडी में कमी से कृषि और सम्बद्ध उत्पादों सम्बन्धी हमारे बढ़ते निर्यात को लाभ होगा। भारत को उन एक तरफा उपायों, जो व्यापार में बाधा डालते हैं, पर एक कठोर बहुपक्षीय अनुशासन से भी लाभ होगा। उरुग्वे बातचीत के सफल समापन से भारत और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समग्र हितो की बहुपक्षीय व्यापारिक व्यवस्था को मजबूती मिलनी चाहिए। प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा के लिए बजट में 53 प्रतिशत की वृद्धि, स्वास्थ्य के लिए 60 प्रतिशत, समन्वित बाल विकास सेवा (आई. सी. डी. एस.) सहित परिवार कल्याण के लिए 28 प्रतिशत और जवाहर रोजगार योजना (जे. आर. वाई.) सहित समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.) के बजट में 63 प्रतिशत की वृद्धि की गयी। निर्धनता उन्मूलन और रोजगार सृजन के चल रहे कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान की जा रही है और उन्हें निर्धनों तथा अधिक पात्र वर्गों के पक्ष में दिशा दी जा रही है। 1752 दूरस्थ और पिछड़े ब्लाकों में, जहाँ संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू है, कार्यान्वित किये जाने के लिए अगस्त, 1993 में एक रोजगार बीमा योजना की घोषणा की गयी।

शेष पृष्ठ 62 पर

तैयार करवाये,

(3) कंपनी को बन्द करने के बारे में निर्णय करे। यदि किसी कार्यशील संस्था के द्वारा अस्वस्थ औद्योगिक इकाई को पुनः स्वस्थ बनाने की योजना तैयार करना तय होता है तो निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं -

(a) अस्वस्थ्य औद्योगिक कंपनी का पुनर्निर्माण अथवा पुनरुद्धार।

(b) अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनी के प्रबन्ध को उचित व्यवस्था के लिए प्रबन्ध को बदलना या प्रबन्ध अपने हाथ में लेना।

(c) अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनी को किसी अन्य कम्पनी में मिला देना।

(d) अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनी के किसी हिस्से या पूरी कम्पनी को बेच देना या पट्टे पर देना।

(e) वे सभी दूसरे उपाय करना जो अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनी की हालत ठीक करने के लिए उचित हों।

6. औद्योगिक वित्त

उद्योगों को मुख्यतः दो प्रकार की पूँजी की आवश्यकता होती है- स्थिर पूँजी व कार्यशील पूँजी। औद्योगिक वित्त को प्राप्त करने के विभिन्न साधनों को सामान्यतः दो श्रेणियों में बाँटा जाता है-

(अ) आन्तरिक साधन- इसमें निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय है-

1. अंश पूँजी (Share Capital)
2. ऋण पत्र (Debentures)
3. लाभ का पुनर्निवेश

(ब) वाह्य साधन

1. सार्वजनिक जमाएँ
2. व्यापारिक बैंक
3. औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली विशिष्ट संस्थाएँ।

उद्योग के लिए समुचित वित्त प्रबन्ध हेतु देश में कई महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएँ काम कर रही हैं। इनमें से प्रमुख निम्न हैं-

1. औद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ.सी.)- इसकी स्थापना केंद्रीय बैंकिंग जाँच समिति के सुझाव पर एक विशेष अधिनियम द्वारा 1948 में हुई थी। यह दीर्घकालिक तथा मध्यकालिक साख प्रदान करता है। इसके द्वारा प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता केवल उत्पादन क्षमता में स्थायी सुधार के लिए ही होती है। यह निगम औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कारखाने के लिए जमीन खरीदनें, इमारत बनाने, नई मशीनें खरीदनें अथवा इनमें सुधार आदि के लिए ऋण देता है। औद्योगिक वित्त निगम को 25 वर्ष की अवधि के लिए ऋण देने का अधिकार है परन्तु यह प्रायः 12 से 15 वर्षों के लिए ऋण देता है।

2. भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड- इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका प्रधान उद्देश्य निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को इनके विकास कार्य में सहयोग प्रदान करना है या निजी क्षेत्र की इकाइयों के आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करना है तथा निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में स्वदेशी तथा निजी पूँजी का निवेश प्रोत्साहित करना है। यह पूंजी बाजार को विकसित करता है तथा उद्यमों में निजी स्वामित्व को प्रोत्साहित करता है।

3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक- इसकी स्थापना 1964 में की गयी थी। यह बैंक अन्य सभी निगमों की भांति उद्योगों की स्थापना तथा विकास की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना पुनर्वित्त की व्यवस्था के उद्देश्य से भी की गयी है। औद्योगिक विकास बैंक सम्पूर्ण औद्योगिक व्यवस्था का नेतृत्व करता है और वित्तीय संस्थाओं के कार्यों तथा नीतियों में तालमेल स्थापित करता है। आधारभूत उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। यह सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालिक ऋण दे सकता है। यह पूँजी बाजार से लिए जानें वाले ऋणों की गारंटी कर सकता है।

4. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक- अप्रैल, 1971 में सरकार ने कमजोर स्थिति वाली औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देने और यदि आवश्यक हो तो उनका प्रबन्ध सुधारने की दृष्टि से भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लि. की स्थापना की थी। यह निगम वित्त प्रबन्ध की संस्था मात्र नहीं थी। यह जिन औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता था, उनके तकनीकी एवं प्रबन्धकीय स्तर को सुधारने का प्रयत्न भी करता है।

20 मार्च, 1985 को एक अधिसूचना के द्वारा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम को भारतीय पुनर्निर्माण बैंक में बदल दिया गया।

5. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया- इसकी स्थापना 1963 में की गयी। यूनिटों की बिक्री का कार्य 1 जुलाई, 1964 से प्रारम्भ हुआ था। यह छोटी-छोटी वस्तुओं को एकत्रित कर विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में निवेश करता है. क्योंकि यूनिट ट्रस्ट का 70 प्रतिशत से भी अधिक निवेश औद्योगिक कंपनियों के साधारण तथा पूर्वाधिकार अंशों, ऋणपत्रों आदि में है, अतः यह कहना ठीक होगा कि यह छोटे और मध्यम श्रेणी के बचत कर्ताओं के साधनों का उपयोग उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए करता है। यूनिट ट्रस्ट के माध्यम से निवेश करने पर इन बचतकर्ताओं को अधिक जोखिम नहीं उठाना पड़ता परन्तु लाभांश समुचित मिल जाता है।

पृष्ठ 23 का शेष

मुद्दे और प्राथमिकताएं

गत ढाई वर्षों में काफी उपलब्धियाँ हासिल की गयी हैं। एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट पर काबू पाया गया है। लम्बे समय से विलम्बित सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की गयी है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना शेष रहा है और यह एक स्पष्ट खतरा है कि यदि आर्थिक सुधारों की यह रफ्तार नहीं बनायी रखी जाती तो कुछ समय पहले कठिनाई से प्राप्त किए गये लाभ बहुत आसानी से गवां दिये जायेंगे। सुधार-प्रक्रिया को जारी रखते समय हमें मूल उद्देश्यों, विकास, समानता, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। मूल उद्देश्य भारत के लोगों, विशेषकर निर्धनों के जीवन स्तर को एक सतत् तरीके से ऊँचा उठाना है। तीव्र व्यापक आधार पर वृद्धि ही एक तरीका है जिसके जरिये यह कार्य हो सकता है। निर्धनता के शीघ्र उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए वृद्धि को श्रम-प्रधान होना होगा क्योंकि, निर्धनों के पास श्रम ही प्रमुख और प्रायः एकमात्र संसाधन होता है।

निष्कर्ष

विगत कई दशकों में आए एक गम्भीरतम आर्थिक संकट पर वृहद् समायोजन उपायों और नीतिगत सुधारों के संयोजन से सफलतापूर्वक काबू पाया गया। अर्थव्यवस्था के ढांचे और स्पर्धात्मकता में परिवर्तन लाने तथा उसे तीव्र श्रम प्रधान वृद्धि के मार्ग पर उन्मुख करने की दृष्टि से दूरगामी नीतिगत सुधार आरम्भ किये गये हैं। भुगतान शेष और मुद्रास्फीति के मोर्चों पर काफी सफलता प्राप्त कर ली गई है और आर्थिक वृद्धि को पुनर्जीवित किया गया है, लेकिन आगे का कार्य लम्बा और कठिन है तथा राजकोषीय शिथिलता तथा कारोबार में हमेशा की तरह के दबाव सदैव मौजूद हैं। राजकोषीय जिम्मेदारी और सतत् सुधार के विकल्पों से अधिक मुद्रा-स्फाति कम वृद्धि, भुगतान शेष की पुनरावर्ती समस्याएं आयेंगी और निर्धनता में बढ़ोत्तरी होगी। यदि तीव्र श्रम प्रधान वृद्धि रोजगार-सृजन और निर्धनता कम करने के उद्देश्यों के सफलतापूर्वक अनुसरण और उन्हें प्राप्त करना है, तो इन विकल्पों का कड़ा विरोध करना ही होगा।